वर्ष : 36 अंक : 27 मुँगराबादशाहपुर जौनपुर, शुक्रवार 25 जून से 1 जुलाई 2021 तक पृष्ठ : 8 मूल्य : 1 रुपया

पीएम मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा और गुलाम नबी समेत अन्य नेता मौजूद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज जम्मू–कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा सार्वजनिक न किए जाने से स्पष्ट हो गया है कि वार्ता का दायरा सीमित नहीं होगा। सभी अपने दिल की बात खुलकर कह सकेंगे ताकि जम्मू–कश्मीर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और विकास के स्थायी वातावरण की बहाली का रोडमैप बन सके और राजनीतिक प्रक्रिया को गति दी जा सके। बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया है। इनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 7, लोक कल्याण मार्ग से शुरू हो रही है। बैठक में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और जम्मू–कश्मीर के अन्य नेता मौजूद हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बैठक में जा रहा हूं। मैं वहां मांगों को रखूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। महबूबा मुफ्ती उनकी पार्टी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा उस पर मैं क्यों बोलूं।

जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अहमद मीर और तारा चंद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू–कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक से पहले सीपीआइ–एम के नेता युसुफ तारीगामी ने कहा कि यहां विधानसभा चुनाव कराने से किसने रोका? हमारी आवाम के सामने यह भी मुद्दा है कि हमारी एक दूसरे से नाराजगी हो सकती है लेकिन हम अलग नहीं होना चाहते। सरकार ने बिना किसी से पूछे केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया और बांट दिया।

नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला दिल्ली में पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंचे।

नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे। वह आज बाद में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई जम्मू–कश्मीर के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार जम्मू–कश्मीर के नेताओं की महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक से पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी से मुलाकात की और घाटी में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के जम्मू–कश्मीर नेताओं के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे।

जम्मू–कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक पर जम्मू–कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा, श्मुझे आमंत्रित किया गया है। मान्यताप्राप्त पार्टियां को बुलाया गया है। लोगों के हक, इंसाफ, एकता, भाईचारा, भारत से मजबूती के बारे में बोलना है।चुनाव, लोकतंत्र, मानवाधिकार का सवाल है।श

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के लिए श्रीनगर में अपने आवास से रवाना हुए।

डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (च्क्च्) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह विरोध मुफ्ती के उस बयान के खिलाफ है जो उन्होंने गुपकार की बैठक के बाद दिया था कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में एक हितधारक है। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए।श

बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया

बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया है। इनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा चार पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद, मुजफ्फर हुसैन बेग, डा. निर्मल सिंह और कवींद्र गुप्ता भी शामिल हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना भी इसमें शामिल हैं। अन्य नेताओं में जम्मू–कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीए मीर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–माक्र्सवादी (माकपा) नेता मोहम्मद युसुफ तारीगामी और पैंथर्स पार्टी के प्रो. भीम सिंह को आमंत्रित किया गया है।

अलगाववादियों व पाक को स्पष्ट संदेश

पांच अगस्त, 2019 को जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इससे केंद्र सरकार ने अलगाववादियों और उनके आका पाकिस्तान को संदेश दिया है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मुद्दा है और इस पर वह सिर्फ और सिर्फ जम्मू–कश्मीर के उन दलों से बात करेगी, जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक उस पुरानी कश्मीर नीति में भी बदलाव की पुष्टि करती है, जिसमें हालात सामान्य बनाने के लिए मुख्यधारा के दलों की उपेक्षा कर अलगाववादियों व उनसे संबंधित संगठनों को विश्वास में लेने, उनसे बातचीत की प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा है।

बेहतरी का रास्ता बनेगा

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ और पत्रकार आसिफ कुरैशी ने कहा कि इस बैठक का कोई ठोस नतीजा बेशक न निकले, लेकिन हर मुददे पर खुलकर बात होगी। बैठक जम्मू–कश्मीर की बेहतरी के लिए एक नया रास्ता तैयार करेगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त प्रधानों को लिखा पत्र, मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान पर दें जोर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव की सरकार के मुखिया नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता करने के बाद अब उनको पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से अलर्ट मोड पर रहने को कहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनको बधाई दी है। इसके साथ ही पत्र में सीएम योगी आदित्यनाथने ग्राम प्रधानों से प्रधानमंत्री मोदी के श्मेरा गांव कोरोना मुक्त के ध्येय को साकार करने के लिए अभियानों में अपना योगदान देने का आग्रह भी किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी प्रधानों पत्र लिखकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पहली तथा दूसरी लहर के दौरान ग्राम सभाओं के उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही इन सभी को तीसरी लहर की आशंका के चलते विशेष सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में इन सभी से अपनी–अपनी ग्राम सभा में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेजी के साथ चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गांव में सभी लोगों को निरूशुल्क कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। इसके अलावा हर लक्षण युक्त बच्चों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए गांवों में विशेष सफाई, स्वच्छता और फागिंग अभियान चलाएं। साथ ही शुद्ध पेयजल की जरूरत के बारे में लोगों को जागरूक करें।सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों से पौधरोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव में वृहद पौधरोपण बेहद जरूरी है। इससे गांवों में हरियाली बढने के साथ ही वातावरण भी काफी स्वच्छ होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे।मुख्यमंत्री का यह पत्र प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत रुप से भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के निर्देशन में कोविड–19 जांच और उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाकर महामारी को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। इस काम में ग्राम पंचायतों में गठित निगरानी समितियों की भी अहम भूमिका रही है।

यूपी पुलिस की पूछताछ से पहले ट्विटर इंडिया चीफ ने कर्नाटक हाईकोर्ट में फाइल की रिट याचिका

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पूछताछ किए जाने से पहले ही ट्विटर इंडिया चीफ ने बेंगलुरु में कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष माहेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर कोतवाली में अपने वकील के साथ हाजिर होना है, मगर उससे पहले मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल की गई है। उनके अधिवक्ता ने कहा कि हमने धारा 41–ए . के तहत यूपी पुलिस की नोटिस को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है।

बता दें कि पुलिस की ओर से सीआरपीसी की धारा– 91 के तहत जारी नोटिस के बाद ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी ने पहले जांच में सहयोग का भरोसा देते हुए खुद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन पुलिस ने उन्हें 24 जून की सुबह 10रू30 बजे व्यक्तिगत रूप से विवेचनाधिकारी के सामने हाजिर होने को कहा था। हालांकि, समाचार एजेंसी पीटीआई ने लोनी के सर्कल ऑफिसर अतुल कुमार सोनकर के हवाले से बताया कि माहेश्वरी दिए गए समय पर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे लेकिन वह दोपहर तक पूछताछ के लिए आएंगे।

पुलिस ने ट्विटर इंडिया के रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर को भी आज पूछताछ के लिए तलब किया है। ट्विटर इंडिया के खिलाफ बीते हफ्ते यूपी पुलिस ने एक वायरल वीडियो के मामले में केस दर्ज किया था। वीडियो में अब्दुल समद नामके एक वृद्ध के साथ जोर–जबरदस्ती दिखाई गई। हालांकि, वीडियो को बहुत से पत्रकार और नेताओं ने सांप्रदायिक एंगल से साझा किया, जबकि पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि बुजुर्ग तावीज बेचता था जिसे लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें पीटा गया। इस मामले में ट्विटर के अलावा राणा अयुब, सबा नकवी, सलमान निजामी, शमा मोहम्मद, मश्कूर उस्मानी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

किस आधार पर राज्यों को आवंटित की जाती है कोरोना रोधी वैक्सीन, केंद्र सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि किघ्सी राज्य को कोरोना रोधी टीकों का आवंटन उसकी आबादी, केस लोड, इस्त्तेमाल की दक्षता और वैक्घ्सीन की बर्बादी कारकों के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें कोविड–19 रोधी वैक्घ्सीन के गैर–पारदर्शी वितरण का आरोप लगाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को कोरोना रोधी टीकों के गैर–पारदर्शी वितरण का आरोप पूरी तरह से बिना किसी आधार के हैं।

केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया किघ् वैक्घ्सीन की बर्बादी से आवंटन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, केस लोड, उपयोग दक्षता और अपव्यय कारकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से कोविड–19 रोधी टीकों का आवंटन जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान और ˜भ् के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाया गया है।

इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और लोगों की भागीदारी के माध्यम से चलाया जा रहा है।

केंद्रीय स्घ्वास्घ्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में राज्यों को ब्टप्फ–19 रोधी टीकों के गैर–पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है। ऐसे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। भारत सरकार पारदर्शी तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्टप्फ–19 रोधी टीकों का आवंटन करना जारी रखे हुए है। भारत सरकार द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा खपत, उनके पास उपलब्ध वैक्सीन की खुराक के साथ–साथ पाइपलाइन में वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है।

केंद्र सरकार की ओर से साझा की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 30 करोड़ (30,33,27,440) से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की जा चुकी हैं। इनमें वैक्घ्सीन की बर्बादी की 28,43,40,936 खुराकें शामिल हैं। इस बीच देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 54,069 केस सामने आए हैं जबकि इस दौरान 1321 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देश भर में अब तक कुल तीन करोड़ 82 हजार 778 लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि तीन लाख 91 हजार 981 लोगों की मौत हुई है।

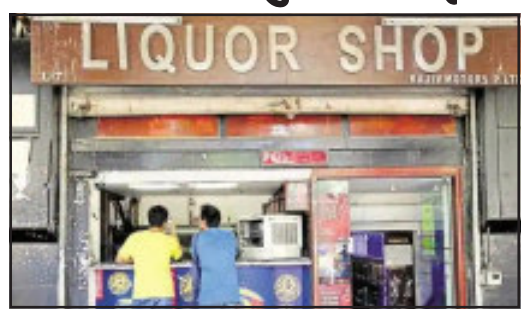

सरकार नहीं बता सकती हमें क्या खाना है और क्या पीना है, शराबबंदी के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी

अहमदाबाद। गुजरात में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर लगी रोक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केस की सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह का कानून अतार्किक, मनमाना, बेवजह और भेदभावपूर्ण वाला है। यही नहीं याची का कहना था कि यह एक तरह से निजता के उल्लंघन जैसा है और राज्य सरकार नहीं बता सकती कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या पानी चाहिए। यही नहीं याची ने कहा कि प्रदेश में रोक के बावजूद एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जो राज्य में शराब की सप्लाई सुनिश्चित करा रहा है।

राजीव पटेल और दो अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निजता की बात करें तो इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 21 में किया गया है। इसके तहत एक नागरिक के पास इस बात का अधिकार का है कि वह कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहता है। इस बारे में सरकार नहीं बता सकती कि उसे क्या पानी चाहिए और क्या खानी चाहिए। इसके जवाब में सरकार की ओर से पेश वकील कमल त्रिवेदी ने कहा कि किसी अदालत के पास यह अधिकार नही है कि वह किसी ऐसे कानून की वैधता की समीक्षा करे, जिसे उच्चतम न्यायालय की ओर से भी बरकरार रखा गया है।

बता दें कि गुजरात में शराबबंदी का कानून 1949 से लागू हुआ था और इसे 1951 में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे बनाए रखने का फैसला लिया था। त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले में निजता का तर्क देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक वातावरण के लिहाज से लगाई गई जरूरी पाबंदियां हैं। उन्होंने कहा कि चारदीवारी के भीतर नॉन–वेज खाने की तुलना शराब पीने से नहीं की जा सकती, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है और उसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार करें तो कल को कोई कहेगा कि मैं ड्रग लेता हूं तो आपको मेरा उत्पीड़न नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अपनी घर के अंदर ऐसा करता हूं।

कर्नाटक कांग्रेस में भी भारी कलह, आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर मारामारी

बेंगलुरू। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर मारामारी चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार को विधायकों से कहा कि वे उन्हें आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश न करें। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मैं फिर भी पार्टी के विधायकों से अनुरोध करूंगा कि वे अगले मुख्यमंत्री के रूप में बयान न दें। इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के बीच सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच एकतरफा खेल शुरू हो गया है।

सिद्धारमैया का बयान उन विधायकों की बढ़ती सूची के बीच आया, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के फरमान के बावजूद खुले तौर पर उन्हें सीएम चेहरे के रूप में समर्थन दिया, जिसने शिवकुमार को नाराज कर दिया, जो मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर रहे हैं।

सिद्धारमैया ने शिवकुमार के बयान पर एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले विधायकों पर लगाम लगाने के लिए कहा गया है।

वहीं, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद नई दिल्ली से लौटने पर, शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया कुछ विधायकों के खुले बयानों पर गौर करेंगे और अपने को मुख्यमंत्री पद पर आगे रखेंगे।बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच सीएम चेहरे के तौर पर सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार को लेकर आवाज तेज होने लगी थी। जहां दोनों खेमे अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर आप आगे रख रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दो अलग अलग खेमे बने हुए हैं।

घमासान के बाद पंजाब के कांग्रेस विधायक बाजवा ने ठुकराया बेटे की नौकरी का आफर, सुनील जाखड़ व दो मंत्रियों पर साधा निशाना

चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक फतेह सिंह बाजवा ने अपने बेटे अर्जुन बाजवा को इंस्पेक्टर लगाने के ऑफर को लौटाते ही अपनी ही पार्टी के प्रधान सुनील जाखड़, मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया और मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा से सवाल किया है। कहा कि उनके बच्चों ने अपने दादा की शहादत के बावजूद नौकरी लौटाकर नई प्रथा शुरू की है। क्या वह भी अपने–अपने भतीजे और बेटों को उन पदों से हटाएंगे जो उन्होंने किसी और सीनियर कांग्रेसी नेता का हक मार कर लिए हैं।

आज यहां अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि सुनील जाखड़ ने अपने भतीजे अजयवीर जाखड़ को पंजाब किसान आयोग का चेयरमैन, सुख सरकारिया ने अपने भतीजे को अमृतसर का जिला परिषद का चेयरमैन और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने अपने बेटे को गुरदासपुर के जिला परिषद का चेयरमैन बनाया हुआ है।

उन्होंने कहा कि मुझे अपने विरोधियों द्वारा अपने ऊपर किए गए हमले का दुख नहीं है, लेकिन मेरे अपने ही साथी इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है। उन्होंने कहा कि मैंने तो कैबिनेट में एजेंडा लाए जाने से पहले ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैसेज भेजकर कह दिया था कि उनके बेटे को नौकरी देने वाले एजेंडे को वापस ले लिया जाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेरे पिता सतनाम सिंह बाजवा की शहादत को आदर देते हुए मेरे बेटे अर्जुन बाजवा को इंस्पेक्टर की नौकरी पर लगाया था। जिस पर हमारी अपनी ही पार्टी के नेता मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें शोभा नहीं देता।

उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ ने खुद उन्हें फोन करके कहा कि उनके व्यक्तिगत तौर पर मतभेद उनके बड़े भाई प्रताप सिंह बाजवा से हैं उनसे नहीं। बल्कि अर्जुन बाजवा ने तो मेरे चुनाव में मेरी मदद भी की थी। मैंने जवाब में उनसे कहा कि यह बात सोनिया गांधी को पत्र लिखने से पहले करनी चाहिए थी।

अर्जुन ने कहा– मुझे शर्म आ रही

इससे पहले अर्जुन बाजवा ने कहा कि जिस तरह से मुझे नौकरी देने के नाम पर सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं उसे देखकर मुझे शर्म आ रही है। अपने दादा की शहादत पर मैं ऐसी सौ नौकरियां वारने को तैयार हूं। अर्जुन बाजवा ने कहा कि नौकरी लौटाने का हमारे परिवार का कलेक्टिव फैसला है। लोग मुझे नौकरी मिलने के बारे में तो बातें कर रहे हैं लेकिन कोई अपने पिता या दादा के शहीद होने की बात नहीं कर रहा। लोग मेरी एजुकेशन नहीं देख रहे, मेरे अमीर होने पर मुझे ताने मार रहे हैं। पुलिस की नौकरी आसान नहीं है।

उन्होंने कहा कि क्या मुझे अकेले को नौकरी मिली है। इससे पहले 1300 लोग अनुकंपा के आधार पर नौकरी ले चुके हैं। मैंने तो फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली थी।

सेंगर की पत्नी के बाद अब करीबी अरुण सिंह को उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिलने पर बवाल

लखनऊ। उन्नाव की राजनीति में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर बवाल होना स्वाभाविक है। माखी के चर्चित दुष्कर्म कांड के मामले में दिल्ली की जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को जिला पंचायत सदस्य के रूप में वार्ड नम्बर 22 फतेहपुर चौरासी से टिकट मिलने और कटने के बाद अब भाजपा से सेंगर के करीबी अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित होने के बाद बवाल हो रहा है। इस बार माखी दुष्कर्म कांड की पीड़िता ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से अरुण सिंह का टिकट काटने का अनुरोध किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 26 जून को होना है, जबकि मतदान तीन जुलाई को होगा।

उन्नाव के माखी गांव की दुष्कर्म पीड़िता अरुण सिंह को उन्नाव से भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाते ही भड़क गई है। उन्नाव में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित होते ही माखी दुष्कर्म कांड का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया। बुधवार रात टिकट की घोषणा होने की सूचना के बाद दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इसमें दुष्कर्म पीड़िता ने कहा कि भाजपा सरकार मेरे साथ है या मुझको लेकर दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ। भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट दे रही। अरुण सिंह मेरे पिता की हत्या में नामजद हैं, जो मेरे खिलाफ है। यह मेरी जान के लिए खतरा बने हैं। पिता की हत्या के अलावा सामूहिक दुष्कर्म में भी अरुण शामिल रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनका टिकट वापस ले।

उन्नाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद सत्ताधारी भाजपा ने बुधवार देर रात उन्नाव से अरुण सिंह को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित कर दिया। अरुण सिंह के भाजपा से प्रत्याशी बनाये जाने के बाद माखी दुष्कर्म कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस कांड में दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हत्या और उसके बाद रायबरेली में हुए सड़क हादसे में पीड़ित की मांग और उसके चाचा की तरफ से दर्ज कराई गई एफआइआर में अरुण सिंह को भी नामित किया गया था। दुष्कर्म पीड़ित का आरोप है कि अरुण सिंह को उम्मीदवार बनाने से उसकी जान को खतरा बढ़ गया है। पीड़ित ने फोन पर वार्ता में कहा कि वह भाजपा नेतृत्व को इसके लिए पत्र लिख रही है। माखी दुष्कर्म कांड की पीड़ित ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी करने के साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अरुण सिंह का टिकट वापस लेने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि भाजपा ने उसे मरवाने के लिए अरुण सिंह को टिकट दिया है।इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत ने कहा कि मेरे हिसाब से उस मामले में अरुण सिंह की कहीं से कोई भूमिका नहीं रही है। अरुण सिंह को कहीं से भी दोषी नहीं ठहराया गया है, वह जांच में निर्दोष साबित हो चुके हैं। यह विपक्षियों की भाजपा को बदनाम करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है।अरुण सिंह फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के दामाद हैं। यहां के नवाबगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह को भाजपा ने उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के मुख्यमंत्री के विज़न की चर्चा देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रही: एम0एस0एम0ई0 मंत्री

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग (एम0एस0एम0ई0) ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। एम0एस0एम0ई0 विभाग ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रिलीफ मिलते ही एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के लिए ऑनलाइन ऋण मेले के आयोजन का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित ऋण मेले की तर्ज पर ही एक महीने के अन्दर सभी 75 जनपदों में भी ऋण मेले का आयोजन किया जाए, इन आयोजनों से प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक आदि को भी जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रथम चरण में भी एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा बैंकों के साथ समन्वय करके एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण वितरण कराया था, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए। सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। राज्य सरकार ने 04 लाख से अधिक युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियोजित किया है। एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किये गये। साथ ही, अन्य उपायों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में असीम क्षमता है। इन्हें प्लेटफॉर्म सुलभ कराए जाने की आवश्यकता है। एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। राज्य के युवा एवं यहां वापस आए श्रमिक व कारीगर अब अपनी उद्यमिता से प्रदेश को लाभ पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी में संसाधन कम पड़ जाते हैं। कोरोना महामारी के सामने दुनिया की बड़ी–बड़ी ताकतें पस्त हो गयीं, किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती से कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तथा दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा सुरक्षित स्थिति में रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दवा, वेण्टीलेटर, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के माध्यम से भरपूर सहयोग किया गया। किसी महामारी के विरुद्ध पहली बार इतनी जल्दी मात्र 09 महीने में वैक्सीन बना ली गयी। 16 जनवरी, 2021 से भारत में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन प्रारम्भ हो गया। इसके परिणामस्वरूप कोरोना संक्रमण की सेकेण्ड वेव का मजबूती से सामना किया जा सका।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सम्बन्ध में कोरोना संक्रमण को लेकर अनेक आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं। कहा जा रहा था कि यहां प्रतिदिन डेढ़ लाख केस आएंगे। मई के अन्त तक एक्टिव मामलों की संख्या 30 लाख से अधिक होगी। राज्य सरकार द्वारा सभी के सहयोग एवं सामूहिक प्रयास से संक्रमण पर नियंत्रण में सफलता प्राप्त की। स्वयं मैंने एवं मंत्रिगण ने प्रदेश भ्रमण किया। राज्य में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 03 लाख 10 हजार तक सीमित रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 24 घण्टे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 208 मामले आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या भी 3600 से कम है। यह याद रखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण से बचाव के लिए अभी भी पूरी सतर्कता व सावधानी बरतें जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता, तब तक टेस्टिंग की कार्यवाही जारी रहेगी। लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जाता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार जीवन एवं जीविका बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना वैक्सीनेशन इसके संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। जीवन को बचाने के लिए वैक्सीनेशन तथा जीविका बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के स्वरोजगार कार्यक्रम से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मिशन शक्ति कार्यक्रम भी सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन ऋण मेले में 31 हजार 542 एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 2505.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत 05 लाभार्थियों को निःशुल्क उन्नत टूल किट भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा इस अवसर पर ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 09 जनपदों–भदोही, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मीरजापुर, मैनपुरी, मऊ, आगरा, बिजनौर तथा मुजफ्फरनगर में 73.54 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से निर्मित होने वाले सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) का शिलान्यास एवं ओ0डी0ओ0पी0 सी0एफ0सी0 योजना के पोर्टल कपनचउेउम.नचेकब.हवअ.पद का शुभारम्भ भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जनपद भदोही, आगरा एवं गाजियाबाद के सामान्य सुविधा केन्द्रों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने जनपद भदोही के सामान्य सुविधा केन्द्र से जुड़े भदोही वूलेन एसोसिएशन, जनपद आगरा के सामान्य सुविधा केन्द्र से सम्बन्धित आगरा शू आर्टिजन्स एसोसिएशन तथा जनपद गाजियाबाद के सामान्य सुविधा केन्द्र से सम्बद्ध ए0के0जी0 फाउण्डेशन फॉर इनोवेशन एण्ड प्रोडक्ट डेवलेपमेन्ट के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के उद्यमी एवं कारीगर अपने परिश्रम से प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। राज्य सरकार इन इकाइयों की हर सम्भव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जनपद गोरखपुर के लाभार्थी शम्सुद्दीन मोहम्मद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जनपद वाराणसी की लाभार्थी मंदाकिनी प्रकाश, जनपद ललितपुर के लाभार्भी श्री आकाश जैन, जनपद मथुरा के लाभार्थी सुश्री अनुष्का, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के जनपद प्रयागराज के लाभार्थी श्री स्वास्तिक गुप्ता तथा जनपद कानपुर देहात के लाभार्थी ज्ञान सिंह कुशवाहा से भी संवाद किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एम0एस0एम0ई0 विभाग ने विगत 04 वर्षों में स्थानीय हुनर के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किये हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को व्यापक पैमाने पर ऋण वितरण किया गया। देश भर में इस पहल की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राज्य की एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया है।

श्री सिंह ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के मुख्यमंत्री के विज़न की चर्चा देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बड़ी संख्या में न केवल रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, बल्कि यहां से होने वाले निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत 04 वर्षों में विभिन्न इकाइयों को 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया है। साथ ही, 02 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस वर्ष का पहला ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम है। इस अवसर पर 31 हजार 542 एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 2505.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा रहा है। विगत वर्ष कोरोना के समय भी बैंकों के सहयोग से 34 हजार से अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 73 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया था।

इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ऋण वितरण के साथ ही सामान्य सुविधा केन्द्र का शिलान्यास किया गया है। यह केन्द्र हस्तशिल्पियों, छोटे उद्यमियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

कुशल प्रशासक की प्रतिमूर्ति थे छत्रपति शिवाजी: संजय

लखनऊ। छत्रपति शिवाजी महाराज साहस राजकौशल और कुशल प्रशासक की सनातन प्रतिमूर्ति थे। वह एक कुशल रणनीतिकार थे। हर युद्ध में उनकी नई रणनीति होती थी, छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाईयों की सहायता से एक प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया।

उक्त बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री संजय बुधवार को सरस्वती कुंज निरालानगर स्थित प्रो. राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया डिजिटल सूचना संवाद केंद्र में हिन्दू साम्राज्य दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कहीं। कोरोना वायरस के कारण आरएसएस और विद्या भारती के प्रचारक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़े थे। संजय ने इतिहास की कई बातों का जिक्र करते हुए छत्रपति शिवाजी के जीवन काल पर प्रकाश डाला। कहा कि 23जून के दिन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 1674 को छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए हिन्दू समाज हिन्दू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाता है। इस दिवस की पुनरू शुरूआत आरएसएस के संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसका उद्देश्य संस्कृति, सभ्यता और सौहार्द के प्रति जागरूक करना है।कहा कि शिवाजी महाराज बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया और लक्ष्य को प्राप्त किया। वह राष्ट्र रक्षा के संघर्ष का प्रतीक बिन्दु थे। कहा कि हमारे देश के इतिहास को तोड़–मरोड़कर पेश किया गया। अंग्रेजों और वामपंथियों ने शिवाजी महाराज के बारे में गलत तथ्य पेश किये, ताकि समाज में प्रेमभाव उत्पन्न न हो सके। इस मौके पर विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश फिल्म विभाग की ओर से बनाई गई शिवाजी की डाक्युमेंट्री भी दिखाई गई। कार्यक्रम का संचालन विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख सौरभ मिश्रा ने किया। इस कार्यक्रम में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की तकनीकी टीम, व्यवस्थापक और कई कर्मचारी मौजूद रहे।

आरएसएस ने हिन्दू साम्राज्य दिवस को उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक व विभाग प्रमुख सुबंधु ने शिवाजी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके शौर्य से जुड़े कई प्रेरक प्रसंग सुनाए। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रामय, रजनीश पाठक, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के बालिका शिक्षा प्रमुख उमाशंकर ,प्रदेश निरीक्षक राजेन्द्र बाबू सहित कई प्रचारक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बस अड्डे पर खाली पडे दुकानों को किराये पर उठायें: एएमडी

लखनऊ। यूपी रोडवेज की एएमडी आईएएस सरनीत कौर ब्रोका ने बुधवार को कैसरबाग डिपो कार्यशाला, अवध डिपो कार्यशाला और कैसरबाग बस स्टेशन का निरीक्षण किया गया। अपर प्रबन्ध निदेशक ने दोनों डिपो में बसों के रखरखाव, सफाई–धुलाई, बस बॉडी रिपेयर व मेन्टीनेंस तथा दैनिक चेकिंग आदि व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कैसरबाग डिपो में बसों का डीजल फ्यूल ऑटोमेशन व्यवस्था को भी देखा। अवध डिपो में जनरथ एसी बसों तथा पिंक महिला एसी बसों का भी निरीक्षण किया गया। अवध डिपो कार्यशाला में फर्श के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। फिर एएमडी ने कैसरबाग बस स्टेशन का निरीक्षण किया जहां यात्री सुविधाओं में गुणात्मक सुधार, साफ–सफाई व्यवस्था, यात्री विश्रामालय, यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की अध्यावधिक समय सारणी को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बस स्टेशन में खाली पड़ी दुकानों व स्टाल को भी किराये पर उचित माध्यम से उठाये जाने को कहा। निरीक्षण के दौरान जयदीप वर्मा, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिवक), आरएन वर्मा (उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता), पल्लव बोस (क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ), सत्य नारायण (सेवा प्रबन्धक लखनऊ), विमल राजन (सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कैसरबाग डिपो), आरएन गोस्वामी (सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, अवध डिपो) और रमेश चन्द्र विष्ठ सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बस स्टेशन कैसरबाग मौजूद रहें।

303 लोगों का हुआ टीकाकरण

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन में आयोजित कोविड संक्रमण से बचाव को लगाये गये टीकाकरण शिविर में बुधवार को 18 से 44 आयु वर्ग में 270 तथा 45 से अधिक आयु वाले लागों को 33 टीके लगाये गये। शिविर में कुल 303 लोगों का टीकाकरण किया गया। अधिक से अधिक लोगों का इसका लाभ मिल सके, इसके लिए टीकाकरण शिविर 26 जून तक बढ़ाया गया है। टीकाकरण शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। शिविर सुचारू रूप से टीका लगाने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सुबह साढे" नौ बजे से लोगों को निर्धारित कोटे के टोकन वितरित किये जायेंगे।

सम्पादकीय

बहिष्कार नहीं, बात करें

जम्मू–कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने एवं उसे केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के करीब दो साल बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब वहां राजनीतिक अनिश्चितता खत्म करने की पहल की है। इसी दिशा में बढ़ते हुए केंद्र ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा परिसीमन है। असल में राज्य को दो हिस्सों में बांटने के बाद जम्मू–कश्मीर में चुनाव कराने के लिए विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जरूरी हो गया था। चुनावी दृष्टिकोण से परिसीमन एक अहम प्रक्रिया है। गौरतलब है कि 6 मार्च, 2020 को गठित परिसीमन आयोग को इस साल मार्च में एक साल का विस्तार दिया गया था। जनसंख्या बदलाव के साथ सभी को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाता है। इस प्रक्रिया के जरिये विधानसभा सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है। परिसीमन की इस प्रक्रिया में क्षेत्र विशेष के राजनेताओं का प्रतिनिधित्व जरूरी होता है। परिसीमन के लिहाज से तो यह बैठक अहम है ही, इसके साथ ही इस सरहदी प्रदेश में आम जनता की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना और जम्मू–कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए नीति बनाना भी सत्ता एवं सियासत का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदलीय बैठक के लिए केंद्र से मिले न्योते पर भले ही अभी तक एक राय नहीं बन पाई हो, लेकिन किसी ने भी बैठक के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया है, जो कि एक अच्छी पहल है। सभी सियासी दल बैठक में शामिल होने के लिए अपने नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पीडीपी ने जहां अपनी नेता महबूबा मुफ्ती पर फैसला छोड़ दिया है, वहीं नेशनल कानफ्रेंस मंगलवार यानी 22 जून को इस विषय में कोई फैसला लेगी। इस बीच, इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया, श्कांग्रेस पार्टी का रुख जो कल था, उसे पुनरू दोहराया जा रहा है कि जम्मू–कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।य यहां उल्लेखनीय है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग अन्य विपक्षी दल भी कर रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि परिस्थितियां सामान्य होते ही जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी पूर्ण राज्य बनाये जाने पर किसी भी दल को आपत्ति है ही नहीं, इसलिए इस मुद्दे को उछालना गैर वाजिब ही होगा। दरअसल अनुच्छेद–370 हटने और केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू–कश्मीर में सियासी हलचल पर सबकी नजर है। लंबी नजरबंदी के बाद तमाम नेताओं की रिहाई एवं जिला विकास परिषद के चुनावों के सफल संचालन के बाद जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। इसी बदलाव के बीच आगे की रणनीति के लिए केंद्र ने बैठक बुलाई है। बेशक गुपकार संगठन अभी तक केंद्र के न्योते पर आम राय नहीं बना पाया है और अनेक दल पूर्ण राज्य के दर्जे की ही अपनी मांग दोहरा रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि बातचीत की टेबल पर सभी लोग मिलें। बैठक के बहिष्कार के बजाय किसी भी मुद्दे का हल वार्तालाप से ही निकलेगा। बातचीत के दौरान ही अपनी शिकायतों को भी दर्ज कराया जा सकेगा और इसके बाद भविष्य की रणनीति बनाने में भी सियासी दलों को आसानी होगी।

दवा उद्योग को संबल हेतु बने रणनीति

भरत झुनझुनवाला

वर्ष 1970 में भारत में बिकने वाली दवाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दो–तिहाई हिस्सा था। इसके बाद सरकार ने प्रोडक्ट पेटेंट को निरस्त कर दिया। पेटेंट, यानी नये आविष्कारों को बेचने के एकाधिकार दो तरह से बनाए जाते हैं। श्प्रोडक्ट्य पेटेंट में आप जिस माल (प्रोडक्ट) का आविष्कार करते हैं और उसे पेटेंट करते हैं, उस माल को कोई दूसरा बनाकर नहीं बेच सकता। इसके विपरीत श्प्रोसेसय्य पेटेंट में आप किसी माल को पेटेंट नहीं करते बल्कि उसको बनाने की प्रक्रिया अथवा तकनीक (प्रोसेस) को पेटेंट करते हैं। प्रोसेस पेटेंट की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति पेटेंट किये गए माल को किसी दूसरे प्रोसेस से बना सकता है। जैसे मान लीजिए आपने लोहे को गर्म करके सरिया बनाने का पेटेंट ले लिया। प्रोडक्ट पेटेंट के अनुसार दूसरा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया से सरिया नहीं बना सकता लेकिन प्रोसेस पेटेंट के अनुसार दूसरा व्यक्ति लोहे को पीटकर सरिया बनाने को स्वतंत्र है क्योंकि आविष्कारक ने लोहे को गर्म करके सरिया बनाने का पेटेंट ले रखा है; सरिये के प्रोडक्ट का पेटेंट उसे नहीं दिया गया है। प्रोसेस पेटेंट में दूसरी तकनीक से कोई व्यक्ति उसी माल को बना सकता है।

70 के दशक में भारत सरकार ने देश में प्रोडक्ट पेटेंट को निरस्त कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि जो दवाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना रही थीं और बेच रही थीं, चूंकि उनके पास उन दवाओं के प्रोडक्ट पेटेंट थे; उन्हीं दवाओं को दूसरी तकनीक से बनाकर बेचने को भारतीय कंपनियां स्वतंत्र हो गईं। परिणाम यह हुआ कि भारतीय कंपनियों ने उन्हीं दवाओं को नयी तकनीकों से बनाना शुरू किया और 1991 में तैयार दवा जिसे श्फॉर्मूलेशन्य्य कहते हैं, उसमें भारतीय कंपनियों का दबदबा भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में स्थापित हो गया। साथ–साथ दवाओं को बनाने वाले कच्चे माल जिसे श्एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स्य्य या एपीआई कहते हैं, उनका 99 प्रतिशत उत्पादन भारत में होने लगा और केवल 1 प्रतिशत आयात किया जाने लगा।

इसके बाद 1995 में सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत प्रोडक्ट पेटेंट को पुनरू लागू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1991 में हम जो केवल 1 प्रतिशत एपीआई को आयातित करते थे, वह 2019 में बढ़कर 70 प्रतिशत होने लगा। भारत इस बाजार से लगभग बाहर हो गया। फॉर्मूलेशन यानी तैयार दवा में कमोबेश ऐसी ही स्थिति बन गयी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के शक्तिवेल सेल्वाराज की मानें तो अगले 6 वर्षों में तैयार दवा भी भारी मात्रा में आयातित होने लगेगी और इस क्षेत्र में भी चीन का दबदबा स्थापित हो जाएगा।

इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने अगले 6 वर्ष में 6,940 करोड़ रुपये दवाओं के उत्पादन की बुनियादी संरचना बनाने में निवेश करने का ऐलान किया है। 19 मेडिकल उपकरणों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। ये दोनों कदम सही दिशा में हैं परंतु ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हैं।

वर्ष 1970 में भारत में बिकने वाली दवाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दो-तिहाई हिस्सा था। इसके बाद सरकार ने प्रोडक्ट पेटेंट को निरस्त कर दिया। पेटेंट, यानी नये आविष्कारों को बेचने के एकाधिकार दो तरह से बनाए जाते हैं। श्प्रोडक्टTM पेटेंट में आप जिस माल (प्रोडक्ट) का आविष्कार करते हैं और उसे पेटेंट करते हैं, उस माल को कोई दूसरा बनाकर नहीं बेच सकता। इसके विपरीत श्प्रोसेसTM पेटेंट में आप किसी माल को पेटेंट नहीं करते बल्कि उसको बनाने की प्रक्रिया अथवा तकनीक (प्रोसेस) को पेटेंट करते हैं। प्रोसेस पेटेंट की व्यवस्था में कोई भी व्यक्तिपेटेंट किये गए माल को किसी दूसरे प्रोसेस से बना सकता है। जैसे मान लीजिए आपने लोहे को गर्म करके सरिया बनाने का पेटेंट ले लिया। प्रोडक्ट पेटेंट के अनुसार दूसरा कोई भी व्यक्तिकिसी भी प्रक्रिया से सरिया नहीं बना सकता लेकिन प्रोसेस पेटेंट के अनुसार दूसरा व्यक्तिलोहे को पीटकर सरिया बनाने को स्वतंत्र है क्योंकि आविष्कारक ने लोहे को गर्म करके सरिया बनाने का पेटेंट ले रखा है; सरिये के प्रोडक्ट का पेटेंट उसे नहीं दिया गया है। प्रोसेस पेटेंट में दूसरी तकनीक से कोई व्यक्तिउसी माल को बना सकता है।

सरकार को और अधिक प्रभावी कदम उठाने होंगे। पहला यह कि दवाओं पर आयात कर बढ़ाने होंगे। यह सही है कि आयात कर बढ़ाने से हमारे देश के नागरिकों को देश में बनी महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन प्रश्न देश की स्वास्थ्य संप्रभुता का है। यदि कुछ समय तक सस्ती आयातित दवाएं न खरीदें और उन्हें स्वयं बनाना शुरू करें तो कुछ समय बाद हम भी सस्ती दवाएं बना लेंगे। इसलिए विषय तात्कालिक बनाम दीर्घकालीन हितों का है। अपनी दीर्घकालिक स्वास्थ्य संप्रभुता को स्थापित करने के लिए हमें कुछ समय के लिए आयात कर बढ़ा देने चाहिए, जिससे इनका उत्पादन देश में होने लगे। इस दिशा में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के राजीव नाथ ने कहा है कि इस वर्ष फरवरी में लागू किए गए बजट से वे निराश हैं क्योंकि मेडिकल डिवाइसों पर आयात कर नहीं बढ़ाए गए। उनके अनुसार घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए आयात करों को बढ़ाना ही होगा।

दूसरा कदम सरकार को नयी दवाओं के आविष्कार में भारी निवेश करना होगा। वर्तमान में कोविड के टीके बनाने वाली दो प्रमुख कंपनियां एस्ट्रेजनेका और फाइजर को उनकी सरकारों ने भारी मात्रा में मदद की है और आज वे उन टीकों को हमें बेचकर बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में हमसे वसूल कर रहे हैं। इनके सामने भारत सरकार ने भारत की अपनी कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक को मात्र 65 करोड़ रुपये की मदद आविष्कार करने के लिए की थी जो सतही मात्र है। सोचिये यदि भारत सरकार ने अपनी 10–20 फार्मा कंपनियों को टीका बनाने को रकम दी होती तो आज हम विश्व के तमाम देशों को टीके का निर्यात करके भारी रकम कमा रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र पर विदेशी सम्मोहन ज्यादा है। पॉली मेडिकेयर के हिमांशु वैद्य के अनुसार भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों को आविष्कार के लिए पर्याप्त मदद नहीं दी है। हमें मान कर चलना चाहिए कि आने वाले समय में कोविड का वायरस म्यूटेंट कर सकता है अथवा नये रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए आगे की रणनीति बनानी होगी और वर्तमान में ही अपने देश में नये आविष्कार के लिए सरकार को निवेश करना होगा।

तीसरा कदम दवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी बुनियादी संरचना में निवेश का है। जैसा ऊपर बताया गया है, सरकार ने 6,940 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है लेकिन हिमांशु वैद्य के अनुसार यह रकम यदि आने वाले 6 वर्षों के अंतिम समय में व्यय की गयी तब तक देश में तैयार दवाओं पर भी चीन का कब्जा हो चुका होगा। तब यह निवेश चिड़िया के खेत चुग लेने के बाद जाल बिछाने जैसा होगा।

चौथा कदम सरकार को भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए रकम सस्ती ब्याज दर पर ऋण अथवा सब्सिडी के रूप में देनी चाहिए। अमेरिकी सरकार ने ईस्टमैन कोडक कंपनी को 5,700 करोड़ रुपये की विशाल रकम 25 वर्ष की मियाद पर दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई बनाने के लिए दी है। विशेष यह कि यह रकम अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के अंतर्गत दी गई है अर्थात अमेरिकी सरकार मानती है कि देश की रक्षा के लिए यह रकम दी जा रही है। इसी प्रकार भारत सरकार को अपनी कंपनियों को एपीआई और फॉर्मूलेशन बनाने के लिए भारी मदद करनी चाहिए अन्यथा देर हो जाएगी।

टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में नहीं छोड़ी गई कोई कसरः पुलेला गोपीचंद

नई दिल्ली। भारतीय एथलीटों के आत्मविश्वास का तेजी से बढना स्वाभाविक है क्योंकि वे अगले महीने टोक्यो में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध खिलाडियों में अपार आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अधीरता को सभी देख व महसूस कर सकते हैं, जो महामारी और इसके कारण पैदा हुई चुनौतियों

के बावजूद उनकी पूरी तैयारी को प्रदर्शित करता है।

लेकिन आश्वासन की यह आभा कहां से आ रही है? एक साल के लिए स्थगित और अब कठिन परिस्थितियों में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 125 एथलीटों में से प्रत्येक ने खेल शुरू होने के पहले शारीरिक, भावनात्मक और प्रतिस्पर्धी रूप से तैयार रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

यह कहना उचित होगा कि हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी, जिन्हें ओलंपिक के लिए चॅलीफाई करने का मौका मिला है, उन्हें वह समर्थन मिला, जो वे चाहते थे। आज, चॅलीफाई करने वाले प्रत्येक बैडमिंटन खिलाड़ी की मदद; एक विदेशी कोच, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच द्वारा की जा रही है। यह स्थिति उस समय से बहुत अलग है, जब खिलाड़ी पर इस तरह के व्यक्तिगत ध्यान की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसकी शीर्ष देश भी आकांक्षा रखते हैं।

मुझे शरियो 2016य की याद आती है, जब भारतीय दल को वांछित परिणाम नहीं मिलने के बावजूद, प्रधानमंत्री ने खिलाडियों को आगे चलकर 100 प्रतिशत प्रदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस ओलंपिक टास्क फोर्स का हिस्सा था, जिसे उन्होंने रियो के लिए नियुक्त किया था। मैं देख सकता हूं कि भारतीय खेल में बदलाव की शुरुआत हो रही है और देश में खेल के सन्दर्भ में सकारात्मक और अधिक पेशेवर माहौल बनाने के लिए उच्चतम स्तर से जमीनी स्तर तक गहरी दिलचस्पी ली जा रही है।

एक उल्लेखनीय बदलाव के रूप में भारत ने एथलीटों को पहले स्थान पर रखा है और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाए। सुधार की गति को बढ़ाया गया है, क्योंकि सभी ने इसे अत्यावश्यक मानकर कार्य किया। इसका एकमात्र उद्देश्य था एथलीटों को खेल के सबसे बड़े उत्सव के लिए अच्छी तरह से तैयार होने में मदद करना है।

राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समन्वय करते हुए, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि कोचों के अनुबंध बढ़ाए जाए। देश भर के उत्कृष्टता केंद्रों में सुरक्षित तरीके से राष्ट्रीय शिविरों का फिर से आयोजन किया गया।

मैं उम्मीद और कामना कर रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक के लिए किये जाने वाले प्रयास सफल होंगे। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है क्योंकि हमने अपने एथलीटों में काफी निवेश किया है। इसका एक अन्य सकारात्मक लाभ यह होगा कि युवाओं को खेल–अपनाने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी, जिससे देश का सम्मान बढ़ेगा। वास्तव में यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम कोविड–19 महामारी के समय में लोगों के चेहरों पर खुशी का भाव ला सकें।

शीर्ष अदालत से सख्त मानदंडों की उम्मीद

अनूप भटनागर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा के दौरान असहाय महिलाओं से कथित सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने सहज ही गुजरात में 2002 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में बेस्ट बेकरी कांड और बिलकिस बानो कांड की याद ताजा कर दी। देखना यह है कि इन पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा या फिर इन्हें भी कानूनी दांव पेचों का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के पीड़ित चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय इनका संज्ञान लेने के बाद इन्हें विशेष जांच दल को सौंपे और मुकदमों की सुनवाई राज्य के बाहर किसी अदालत में कराये। अब सवाल यही है कि क्या पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिये गैर सरकारी संगठन आगे आएंगे और क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और न्यायपालिका इसी तरह का कड़ा रुख अपनायेगी? राज्य सरकार के रवैये से सवाल उठता है कि अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो जनता का क्या होगा? क्या वजह है कि राज्य में हिंसा के दौरान पुलिस मूक बनी रहती है। लोगों का बड़ी संख्या में पलायन होता है और राज्यपाल को इन विस्थापितों से मिलने के लिये दूसरे राज्य में जाना पड़ता है।

हिंसा की घटनाओं की जांच के लिये मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित था और इस दौरान राज्य सरकार इस तरह की किसी भी घटना को नकारती आ रही थी। लेकिन उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ इससे संतुष्ट नहीं थी। पीठ ने अंततरू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसकी जांच का काम सौंपा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मानव अधिकार आयोग के जांच दल के साथ हर तरह का सहयोग करे। उम्मीद है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ पूरा सहयोग करेगी।

आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद फिर से सत्तासीन हुई तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों ने प्रदेश के कई इलाकों में भाजपा का समर्थन करने वाले लोगों के घरों और उनके परिवारों को निशाना बनाया। उनके घरों में लूटपाट की और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पूर्वी मिदनापुर की 64 वर्षीय महिला का आरोप है कि चार मई की रात में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसके घर पर धावा बोलकर तोडफ़ोड़ की और फिर उससे सामूहिक बलात्कार किया। सामूहिक बलात्कार की मेडिकल जांच में पुष्टि भी हुई लेकिन इस मामले में नामित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

इसी तरह, यह भी आरोप है कि नौ मई को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया। कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार इन महिलाओं ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की विशेष जांच दल या केन्द्रीय जाच ब्यूरो से जांच करायी जाये और इन मामलों से संबंधित मुकदमों को राज्य के बाहर किसी अदालत को सौंपा जाये ताकि उनके साथ न्याय हो सके। ऐसी ही घटनाएं गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा के दौरान हुई थी। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे के करीब एक दर्जन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिये उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल गठित किया था। शीर्ष अदालत ही लगातार इन दंगों की घटनाओं की जांच की प्रगति की निगरानी कर रही थी।

शीर्ष अदालत के सख्त रवैये का ही नतीजा था कि बेस्ट बेकरी कांड में पहले राउंड में निचली अदालत से जून, 2003 में बरी हो गये अभियुक्तों के खिलाफ फिर से आरोपों की जांच हुई। न्यायालय ने इस मुकदमे की सुनवाई गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में कराई, जिसमें दोषियों को सजा मिल सकी। कमोबेश, यही हाल बिलकिस बानो कांड का भी था। इस प्रकरण में भी गुजरात की अदालत से न्याय नहीं मिलने पर उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई मुंबई की विशेष अदालत को सौंपी। इस विशेष अदालत ने 20 में से 12 अभियुक्तों को बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। देश की शीर्ष अदालत ने सितंबर, 2019 में अपने आदेश में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा देने और उसे सरकारी नौकरी तथा नियमों के अनुरूप आवास उपलब्ध कराने का निर्देश भी गुजरात सरकार को दिया था।मानव अधिकारों की रक्षा के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवेदनशीलता और सक्रियता के मद्देनजर ही पश्चिम बंगाल की ये पीड़ित महिलायें अब इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने और पीड़ितों के लिये उचित मुआवजे की खातिर सर्वोच्च न्यायालय की ओर नजर गढ़ाये हैं।

मास्टर के बाद बीस्ट में दिखेगा थालापथि विजय का धांसू अवतार, पहला लुक देख फैंस हुए क्रेजी

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता थालापथि विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों में काफी ज्यादा व्यस्त है। थालापथि विजय कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले हैं। जिसमें उनकी फिल्म बीस्ट भी शामिल हैं। जिसका पहला लुक सामने आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों फिल्म मेकर्स ने इस बात का खुलासा किया था कि थालापथि विजय कि अपकमिंग फिल्म का पहला पोस्टर 21 जून को रिलीज कर दिया गया। हालांकि अब मेकर्स ने अपना वादा पूरा करते हुए अभिनेता थालापथि विजय की फिल्म बीस्ट का पहला लुक शेयर कर दिया है। थालापथि विजय की फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने टाइटल का भी खुलासा कर दिया। फिल्म का टाइटल बीस्ट रखा गया है।

ये सुपरस्टार विजय की 65वीं फिल्म है इसलिए फिल्म का नाम थलापित 65 रखा गया था लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म का टाइटल का खुलासा कर दिया है। फिल्म का निर्देशन नेल्सन करने वाले है। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म बीस्ट का फर्स्ट लुक सन पिक्चर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

इस पहले लुक में अभिनेता विजय का दमदार अंदाज में नजर आ रहा हैं। विजय ने हाथ में बड़ी सी बंदूक थामी हुई है और उनकी मस्कुलर बॉडी देखकर फैंस फिल्म के पोस्टर को देखकर क्रेजी हो गए है। अब फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। बीस्ट फिल्म को जाने माने निर्देशक नेलसन दिलीपकुमार ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में अभिनेता विजय के साथ अभिनेत्री पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में नजर आने वाली है। अगर हम बात करें अभिनेता के काम की तो उनकी पिछली रिलीज फिल्म मास्टर थी। जो इस साल की शुरूआत मेरे सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था।

तीसरी लहर का इंतजार

प्रदीप कुमार दीक्षित

कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वायरस हमेशा के लिए चला गया है। वायरस अभी भी हमारे बीच घूम रहा है। वह मौके की तलाश में है। अगर फिर से लापरवाही की तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। तीसरी लहर आ सकती है। अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। गुणी लोग यह चेतावनी बार–बार दे रहे हैं।

लेकिन दिशा–निर्देशों को बड़ी संख्या में लोग सिर पर कफन बांध कर पहले भी नहीं मान रहे थे, अब भी सुनेंगे क्या। ऐसे लोगों के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ऐच्छिक ही रहा। कुछ वीरजादे दो–दो बार कोरोना से पीड़ित हुए और फिर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ताल ठोकने लगे।इसी अवधि में एक युवक और एक युवती ने तो पीपीई किट पहन कर सात जन्मों का साथ निभाने के फेरे लिए। युवती के कोरोना पीड़ित होने के बावजूद विवाह हुआ। जब इस जन्म में ही साथ निभ जाने का पक्का नहीं तो भी यह दुस्साहस किया गया। लोगों ने बात–बिना–बात मिलना–जुलना नहीं छोड़ा। चौपाल लगा कर देश–परदेस की चर्चा करते रहे। इसी दौरान चुनाव भी हुए। जनसंपर्क भी हुआ। आमसभाएं भी हुईं। इन सबने कोरोना पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया। इनमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे, जिन्हें कोरोना से संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करना था और जनता से भी करवाना था।लेकिन वे निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के अगुआ बन गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से तो यह कह कर रौब झाड़ा, श्मुझे जानते नहीं हो क्या।य लेकिन कोरोना ऐसे स्वयंभू लोगों को नहीं जानता था। वह ऐसे कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे लोगों ने यमराज के सामने भी रौब झाड़ा होगा कि भैयाजी से बात करवाऊं क्या। यानी ऐसे लोगों को सुधारना आसान नहीं।कुछ लोग छूट मिलते ही बिना सुरक्षा के बाजारों में जा घुसे। जैसे बाजार में मिलने वाला सामान बाद में नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग इस दौर में जोर–शोर से त्योहार मनाने में जुट गए, जैसे अगले वर्ष यह त्योहार आएगा ही नहीं। यह बात अलग है कि त्योहार तो आएगा लेकिन ये जश्न प्रेमी रहेंगे कि नहीं, यह पक्का नहीं है।

ग्राम पंचायत में औषधीय वाटिका की जायेगी तैयार

बीकेटी।लखनऊ। बीकेटी खंड विकास अधिकारी पूजा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में औषधीय वाटिका का निर्माण कराया जाएगा।जिसमें प्रथम चरण में अहमदपुर खेड़ा, सराय दामू ,कठवारा ,बीबीपुर, ,सिंघमऊ, कुम्हरावा ,बेहटा समेत 20 से अधिक ग्राम पंचायतों में औषधीय वाटिका तैयार की जाएगी। इसमें 400000 की लागत का अनुमान किया जा रहा है। पूरे ब्लॉक में इस योजना पर 8000000 व्यय होने की संभावना है।औषधिए युक्त वृक्षा रोपड़ से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। लोगों को मनरेगा के तहत श्रमिकों को काम मिलेगा। इससे श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और वे अपने परिवार का भरण पोषण आसान से कर सकेंगे।बताया वाटिका में देखरेख के लिए केयरटेकर रखा जाएगा।बताया कि औषधीय वाटिका की देखरेख के लिए 90 दिनों के लिए केयरटेकर की तैनाती की जाएगी। इससे बेरोजगारों को काम मिलेगा।इनका भुगतान मनरेगा के तहत किया जाएगा।औषधीय वाटिका में कौन–कौन से पौधे लगाए जाएंगे ,इन औषधियों वाटिका में तुलसी गिलोय अश्वगंधा एलोवेरा तथा अन्य औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इनकी देखरेख प्रधान भी करेंगे,इनमें औषधीय पौधे के अलावा फलदार पौधों का भी रोपण किया जाएगा। नागरिकों का कहना है कि पोषण वाटिका जलालपुर सिंघामऊ या अन्य पंचायतों की पोषण वाटिका में एक पौधा नहीं है।स्थानीय लोगों का कहना है कि देख रेख की सुचारू रूप से व्यवस्था नही की गयी तो स्थिति जस की तस हो जायेगी ।

तालाब में मिला लापता का शव

बीकेटी। लखनऊ शनिवार को सुभाषनगर इटौंजा निवासी आशाराम कठेरिया रात्रि करीब 10 बजे घर से अचानक लापता हो जाने से घरवालों ने लोगों से पूछताछकर खोजबीन की न मिलने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में तहरीर दी कि आसाराम रात्रि से बिना बताए घर से कहीं चले गए हैं ,जिनका कोई अता–पता नहीं है। थाना इटौंजा की पुलिस तहरीर के आधार पर छानबीन किये जाने पर मंगलवार की सुबह 5 बजे घर वालों ने घर के पीछे बने तालाब में उतराता हुआ दिखाई दिये जाने की सूचना थाना इटौंजा को दी।पुलिस टीम द्वारा मौके पहुंच कर शव तैरता हुआ दिखाई दिये जाने पर शव को तालाब से बाहर निकाल कर पहचान की गई तो शव की पहचान आसाराम नाम के व्यक्ति के रूप में पुष्टि की गयी ।पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया। मृतक के घर में पत्नी मंजू देवी व 5 छोटे छोटे बच्चे है, बेटी चाँदनी 16 वर्ष, बेटी मोहनी 10 वर्ष, अंश बेटा 7 वर्ष, आशू 5 वर्ष, जान्हवी 3 वर्ष परिवार में केवल आशाराम ही एक मात्र सहारा था। परिवार को मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। संकट की इस घड़ी में बीकेटी के लोकप्रिय नेता चेयरमैन अरुण सिंह,गप्पू द्वारा 5000 हजार रुपये नगद व 20000 हजार रुपये की चेक देकर आर्थिक सहायता की गई। अरुण सिंह,गप्पू ने आगे भी सहायता करने का आश्वासन दिया। साथ में मौजूद सांसद प्रतिनिधि संदीप शुक्ल पूर्व जिला उपाध्यक्ष, उमेश सिंह कमल, अवस्थी पूर्व मंडल अध्यक्ष मान सिंह, अरुण पांडेय आदि वरिष्ठ लोग रहे मौजूद

लखनऊ –कासगंज स्पेशल 29 से चलेगी

लखनऊ। कोरोना का प्रभाव देश में कम होते ही रेलवे प्रशासन ने वीआईपी यात्रियों के लिए एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों का संचालन धीरे–धीरे चरणों में कर रहा है। इतना ही नही इन यात्रियों के अलावा दैनिक व आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए पैसेन्जर व इण्टरसिटी ट्रेनों का भी संचालन शुरू कर कर रहा है। रेलवे प्रशासन ट्रेन–05380 / 05379 कासगंज–लखनऊ जं0–कासगंज अनारक्षित स्पेशल का संचालन कासगंज से 28 जून से तथा लखनऊ जं0 से 29 जून से अगली सूचना तक किया जायेगा । ट्रेन–05380 कासगंज–लखनऊ जं0 अनारक्षित स्पेशल 28 जून से अगली सूचना तक कासगंज से दोपहर 02.50 बजे रवाना होकर बधारीकलां, सहावर टाउन, गरखा, गंजडुंडवारा, पटियाली, नस्थर, दरयावगंज, बल्लूपुर, रूदायन, कम्पिलरोड, कायमगंज, भटासा, शमसाबाद, सुकुरूल्लाहपुर, हरसिंहपुर गोबा, फर्रूखाबाद, फतेहगढ़, याकूतगंज, कमालगंज, सिंधीरामपुर, खुदागंज, मलिकपुर, गुरसहायगंज, खुदलापुर, जशोदा, जलालपुर, पनवारा, कन्नौज सिटी, कन्नौज, गंगवापुर हाल्ट, अरौल मकनपुर, बकोठीखास, बिल्हौर, घोरसालार, उतरीपुरा, बर्राजपुर, चौबेपुर, मन्धना जंक्शन, कल्याणपुर, रावतपुर, कानपुर अनवरगंज, कानपुर सेण्ट्रल, कानपुर ब्रिज, मगरवारा, उन्नाव जंक्शन, सोनिक, अजगैन, कुसुम्भी, जैतीपुर, हरौनी, दूसरे दिन पिपरसंड, अमौसी तथा मानकनगर से छूटकर लखनऊ जं0 देर रात 01.10 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05379 लखनऊ जं0–कासगंज एक्सप्रेस स्पेशल 29 जून से अगली सूचना तक लखनऊ जं0 से तड़के 04.30 बजे प्रस्थान कर कासगंज दोपहर 02.40 बजे पहुंचेगी । इस स्पेशल ट्रेन में जनरल क्लास के 10 तथा एसएलआर / एसएलआरडी के 02 कोचों सहित कुल 12 कोच लगाये जायेंगे ।

झलकारी बाई अस्पताल में दुरूस्त पायी गई व्यवस्थायें

लखनऊ। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने बुधवार को तयशुदा कार्यक्रम के तहत आयोग सदस्य कुमुद श्रीवास्तव के साथ वीरांगना झलकारीबाई महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर भर्ती महिलाओं को प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही ओपीडी रूम, अल्ट्रा साउण्ड रूम, एक्सरे रूम, लेबर रूम, ओटी रूम, ऑपरेशन रूम, महिला वार्ड, किचन, व मरीजों को दिये जाने वाले भोजन, दवाईयां व अन्य सुविधाओं को परखा। प्रमुख वार्डों में किचन, स्नानागार व शौचालय की सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गयी। अन्त में वैक्सीनेशन एरिया का भी निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि चिकित्सालय में वैक्सीन लगवा रही महिला को सभी जरूरी जानकारी दी जा रही। सीएमएस डॉ. रंजना खरे ने उन्हें बताया कि विगत माह चिकित्सालय में प्रसव को लगभग 345 मरीज भर्ती हुये हैं, 141 नवीन जन्मे शिशु हैं और 203 महिलायें भर्ती हैं। 45 भर्ती महिलाओं के लिये भोजन बनाया गया है। 01 मरीज के साथ 01 ही तीमारदार को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मरीज की स्थिति सामान्य होने पर उसे ग्रीन जोन में भेज दिया जाता है। अध्यक्ष ने डॉ. रंजना खरे को महिलाओं व किशोरियों से सम्बन्धित समस्त लाभकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये इनका स्पष्ट उल्लेख अस्पताल परिसर में कराये जाने के निर्देश दिये। इस दौरान डॉ. दीपा शर्मा चिकित्सा अधीक्षिका, डॉ. पीके मिश्रा, डॉ. दीपक कुमार, पीएस तिवारी, एसएन सिंह व संजय जायसवाल आदि प्रमुख चिकित्सक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में वैक्सीनेशन में गड़बड़ी!

एक व्यक्ति को पहला टीका कोवैक्सीन का तो दूसरा कोवीशील्ड का लगाया

लखनऊ। मेगा टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन का महाअभियान...ऐसे कई बडे" नामों से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का देश–प्रदेश में जन–जन के बीच प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। भारत की आजादी के बाद संभवतरू यह पहला ऐसा वृहद अभियान माना जा सकता है जिसे लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक संजीदा हैं। आलम यह है कि कोरोना की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए खुद पीएम मोदी और सीएम योगी तक नागरिकों से विभिन्न जनसंचार माध्यमों के जरिये रूबरू होते हुए उन्हें टीकाकरण के प्रति जागरुक करते देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि टीकाकरण के इस महाअभियान में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद में ही गड़बड़ी देखने को मिले तो इसे क्या माना जाये। यहां एक व्यक्ति को पहला टीका कोवैक्सीन का जबकि दूसरा कोवीशील्ड का लगा दिया गया। गौर हो कि अभी कुछ ही दिनों पहले सुल्तानपुर जनपद में भी ऐसे कई मामले संज्ञान में आये थे।

दरअसल, बुधवार को सूबे के सिद्धार्थनगर (नौगढ़)जनपद के बढ़नी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) पर उस समय हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति को तो पहले फेज में कोवैक्सीन टीका लगा और जब आज वो तिथि अनुसार दूसरा टीका लगवाने पहुंचा तो ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने उसे कोवीशील्ड टीका लगा दिया। यानी एक व्यक्ति को दो अलग–अलग टीके लगा दिये गये जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऐसे में जब अमुक व्यक्ति को यह सब पता चला तो वो दहशत में आ गया, फिर उसके परिजन भी वहां पहुंचे गये और मौजूद डॉक्टरों से सवाल–जवाब करने लगे।

हालांकि वहां के एक डॉक्टर से बात की गई तो उनका यही कहना रहा कि नर्स से चूक हो गई है, उसकी रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जायेगी। मगर वो डॉक्टर इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सके यदि उक्त व्यक्ति को कुछ हुआ तो उसका जिम्मा कौन लेगा। थक–हारकर और डरा–सहमा वो व्यक्ति अपने परिजनों के साथ वापस घर चल गया और यही सोचता रहा कि आखिर वो आज टीका लगवाने क्यों गया, या फिर वो गया तो इसमें उसकी गलती कहां है। वहीं इस अति गंभीर विषय पर जब जनपद के सीएमओ से लेकर डीजी हेल्थ और यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई तो लब्बोलुआब सबने यही कहा कि मामले को दिखवाते हैं, यानी सीधे तौर पर किसी ने भी स्पष्टतरू इसे मेडिकल टीम की चूक नहीं माना।

बढ़ते ईंधन के दामों से खेती पर मंडराने लगे संकट के बादल

मोहनलालगंज।लखनऊ। डीजल बढ़ोत्तरी के चलते किसानों ने धान रोपाई के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं।क ोरोना काल के संकट में किसान पहले से ही बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर आर्थिक तंगी झेल रहा है ।और अब डीजल के नए दामों ने किसानों को संकट में डाल दिया है ।मौजूदा धान रोपाई का सीजन के चलते ।ट्रैक्टर मालिकों ने भी किराया बढ़ा दिया है।जिससे खेतों की जुताई का भाढ़ा दे पाना छोटे काश्तकारो को मुश्किल हो रहा है ।पिछले कई महीनों से लगातार ईंधन बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी के किसानों ने इस बार धान रोपाई ना करने का मन बना लिया ।डीजल की बढ़ती कीमतें किसान मेवा लाल रावत का कहना है कि केन्द्र व राज्य सरकार किसानो के हित को सिर्फ बड़े–बड़े दावे करती है ,आज किसानो के सामने मंहगाई के संकट से खेती किसानी करना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष खेती पर अधिक खर्च हो रहा है पिछले साल एक बीघा खेतों की जुताई करने के लिए नौ सौ रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक खर्चा होता था जबकि इस वर्ष 14 से 15 सौ रुपए प्रति बीघा खर्च आ रहा है इसी को लेकर किसान असमंजस में फंसा हुआ है की धान रोपाई की जाए अथवा नहीं इसमें ज्यादातर किसान धान रोपाई करने के लिए इंकार कर दिया डीजल के बढ़ते दामों ने किसानों को खेती करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। डीजल 88 .66 रुपए पहुंच गया, महंगाई की बढ़ती मार ने लोगों को बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है उधर पेट्रोल के बढ़ते दामों।डीजल ,पेट्रोल में लगातार दामों की बढ़ोत्तरी जारी अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों पर लगातार अत्याचार कर रही है। महंगाई की चौतरफा मार सिर्फ किसानों पर भारी पड़ रही है।

बागों में पकने वाले फल की समय से तुड़ाई करें: डॉ. तोमर

निदेशक उद्यान ने कहा, दवा छिड़काव के एक हफ्ते बाद करें आम का सेवन

लखनऊ। प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने आम बागवानों के लिए आम की अच्छी पैदावार के मद्देनजर कहा है कि जिन बागों में फल पकने योग्य है उनकी समय से तुड़ाई अवश्य कर ली जाये। जिन क्षेत्रों में सुड़ी व थ्रिप्स का बहुत अधिक प्रकोप दिखाई देता है तो क्लोरपाइरीफास 20 इसी 02 मिली प्रति ली पानी में तथा एंथ्रेकनोज, काला सड़न रोग के बचाव को कार्बेन्डाजिम 01 ग्राम प्रति ली पानी में घोलकर छिड़काव किया जाये। यह जानकारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉ. आरके तोमर ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि बागों में घनापन इनका मुख्य कारण है, इसके लिए पुराने बागों का जीर्णोद्धार, बिरलीकरण या कैनोपी प्रबन्धन भी करने की आवश्यकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि दवा के छिड़काव के एक सप्ताह बाद ही फलों का उपयोग किया जाय। बताया कि आम की फसल में सुड़ी कीट फल में छेद कर गूदे को खाकर क्षति पहुंचायी जाती है जिससे फल सड़ने लगता है। थ्रिप्स कीट द्वारा फल के छिलके को खाकर या खुरच कर हानि पहुंचायी जाती है, जिससे फल में काले धब्बे पड़ जाते है। फल मक्खी कीट परिपक्व फलों में अण्डे देती है जिनसे दो तीन दिन बाद सुडियां निकल कर गुदे को खाना शुरू कर देती है। इनके द्वारा आम के गूदे को खाकर अर्ध तरल बदबूदार पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देती है। एन्थ्रेकनोज रोग के कारण फलों में छोटे–छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते है, जो बाद में पूरे फल को ढ़क लेते है तथा पूरा फल काला होकर सड़ जाता है। इसी प्रकार काला सड़न रोग में शुरूआत में इसके लक्षण पीले रंग के गोल रूप में दिखाई देते है जो बाद भूरे रंग के हो जाते है। यह धब्बें पानी से भीगे दिखाई देते है जो आगे चलकर इन धब्बे का आकार बढ़ जाता है। तथा इनके ऊपर काले रंग की फंफूद देने लगती है। निदेशक, उद्यान ने कहा कि प्रदेश में आम एक मुख्य फसल है वर्तमान में आम की अगेती व मध्य किस्मों में फल पक रहे है। जिनका आम बागवानों द्वारा तुड़ाई कर विक्रय किया जा रहा है।

वजीरगंज में तीन मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबने से एक युवक की मौत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित रिवर बैंक कालोनी में तीन मंजिला इमारत ढह गई। इस दौरान मलबे के नीच दबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू के लिए ैक्थ् टीम को बुलाया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मलबे के नीचे से मजदूर के शव को बाहर निकाला।

रिवर बैंक कालोनी में सूरज कुंड से सटे बना गोमती सदन काफी जर्जर हालत में था। इस इमारत के अगले हिस्से में जिओ फाइबर कंपनी में काम करने वाले गौरव त्रिवेदी अपने चाचा ज्ञानी त्रिवेदी के साथ रहते थे। पुलिस ने बताया कि गौरव बाहर वाले कमरे और ज्ञानी अंदर वाले कमरे में सोते थे।

प्रदेश प्रभारी ने बैठक कर कार्यकताओं को किया प्रेरित

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बुधवार को उत्तर मंडल 5 की बूथ संख्या 292 के बूथ समिति कार्यकताओं के साथ बैठक कर बूथ को मजबूत करने की योजना समझाई। कहा कि पार्टी ने बूथ जीता तो सब जीता की रणनीति बनाई है। चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर जीत की नींव रखें। पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ लगकर चुनाव जीतना है। जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। बूथ स्तर पर प्रत्याशियों को जिताना है, उसके लिए बूथ समितियों को मजबूत करना है।

मिनीषा लांबा को फिर से हुआ प्यार

एक्ट्रेस मिनीषा लांबा ने साल 2005 में फिल्म श्यहांय से बॉलीवुड डेब्यू किया था. हालांकि वह फिल्म बचना ऐ हसीनो, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और वेल डन अब्बा से पॉपुलर हुई. कुछ दिनों पहले ही मिनीषा ने पति के साथ अलग होने का खुलासा किया था. मिनीषा ने साल 2015 में रयान थाम से शादी की थी और दोनों अब अलग हो गए हैं. इस बारे में बात करते हुए मिनीषा ने कहा, श्कभी–कभी 2 लोग साथ नहीं रह सकते और किसी ने कुछ गलत नहीं किया जो हम किसी को ब्लेम करें. कुछ चीजें प्राइवेट रहती हैं और किसी के बारे में कहकर आप सामने वाले के साथ गलत नहीं कर सकतेश्य मिनीषा ने कहा, श्शादी के अंत होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी का अंत हो गया है. आपके पास प्यार करने का एक और मौका होता है. अपने पास्ट को भूलकर आप आगे बढ़ सकते हैं. मैं इसलिए इस बारे में बात कर रही हूं ताकि ऐसी सिचुएशन में फंसे लोगों की मदद हो सकेश्य जब मिनीषा से पूछा गया कि उनका सपोर्ट सिस्टम कौन है तो उन्होंने कहा, श्मेरे पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है मेरे क्लोज फ्रेंड्स और परिवार में है. मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूंश्य जब मिनीषा से पूछा गया कि क्या वह भी प्यार को दूसरा मौका दे रही हैं? तो उन्होंने कहा, श्हां, मैं अभी एक प्यारे इंसान के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हूंश्य लेकिन मिनीषा ने शख्स का नाम नहीं बताया है. मिनीषा जो सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर हैं वह फिलहाल अपने अपकमिंग ओटीटी प्रोजेक्ट को लेकर बिजी हैं. इससे पहले वह बिग बॉस 8 में नजर आई थीं और शो तेनाली रामा से टीवी डेब्यू किया था. इसके बाद साल 2018 में वह इंटरनेट वाला लव में नजर आई थीं. बॉलीवुड से टीवी पर काम करने पर मिनीषा ने कहा था, टीवी पर काम मैं हमेशा से करता चाहती थी और जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसे ले लिया. मुझे टीवी से ऑफर्स आते रहते थे, लेकिन मैं कुछ इंट्रेस्टिंग चाहती थी. मैं डांस रिएलिटी शो और खतरों के खिलाड़ी में भी काम करना चाहती हूं.

इशिता दत्ता ने बागवानी के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की

अभिनेत्री इशिता दत्ता का कहना है कि बागवानी ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान व्यस्त रहने में बेहद मदद की है। इशिता ने कहा मैं जमशेदपुर में बहुत हरियाली के आसपास पली–बढ़ी हूं। हम प्रकृति और पेड़ों से बहुत जुड़े हुए हैं। पुश्तैनी घर में हमारा खुद का एक बगीचा है। मैं कोशिश कर अपनी बालकनी और किचन गार्डन बनाया है। मुझे जहां भी जगह मिलती है, वहां एक पौधा लगाती हूं। अभिनेत्री का कहना है कि पौधे पॉजिटिविटी लाते हैं। वे ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा लाते हैं और उनमें से बहुत से अद्भुत औषधीय मूल्य हैं। मैं अपने मिनी गार्डन से तुलसी, एलोवेरा और कुछ अन्य का उपयोग करती हूं। मैं अपने मिनी गार्डन के बारे में बात कर सकती हूं। यह मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिलाते हैं। उन्होंने सावधानी का एक नोट दिया, चलो सभी प्रोटोकॉल के भीतर रहें। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी हमें मौका मिले, चलो टीकाकरण करवाएं।

जब आप मुंह में चिप्स डालते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं?

चिप्स खाने की आदत बहुतों में विकसित हो चुकी है। कभी–कभी वे चिप्स खाते हैं, सुबह–दोपहर की चाय के साथ, काम पर या फुरसत में, चिप्स उनके साथी होते हैं। अगर आपको लगता है कि चिप्स खाने का कोई समय निर्धारित नहीं है तो आप चिप्स के पैकेट को खोल कर खा सकते हैं. बहुत से लोग भूख को कम करने के लिए नहीं खाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए चिप्स खाना पसंद करते हैं। जब वे कहीं जाते हैं तो चिप्स का एक पैकेट ले जाते हैं।

कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चे को चिप्स के पैकेट सौंपते हैं। जब आप घर जाएं तो दुकान से चिप्स के कुछ पैकेट ले जाएं। कई माता–पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के स्कूल के टिफिन में चिप्स देते हैं। युवाओं में बाजार में तरह–तरह के स्वादिष्ट चिप्स खाने का चलन ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार के इन चिप्स में एक तरह का केमिकल होता है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है!

स्वीडिश नेशनल फूड अथॉरिटी के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि एक्रिलामाइड या एक्रिलामाइड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है जो अनाज या सब्जियों में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट में उच्च होते हैं और उच्च तापमान पर गर्म होने पर उन यौगिकों को बनाने में सक्षम होते हैं। जिस तरह यह रासायनिक यौगिक मानव जीवन काल को कम करने में विशेष भूमिका निभाता है, उसी प्रकार यह कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढने में भी मदद करता है।

हम जानते हैं कि आलू एक प्रकार की उच्च स्टार्च युक्त सब्जी या अनाज है। इन आलूओं को अतिरिक्त नमक के साथ बहुत पतले स्लाइस में काटा जाता है और उन्हें संरक्षित करने के लिए लंबे समय तक तेल में डीप फ्राई किया जाता है। नतीजतन, इसका पोषण मूल्य काफी हद तक खो जाता है। इतना ही नहीं, इस विधि से पैक आलू के चिप्स में एक हानिकारक रासायनिक यौगिक एक्रिलामाइड उत्पन्न होता है। ये रासायनिक यौगिक कैंसर का कारण बन सकते हैं।

दुनिया भर के कई पोषण विशेषज्ञ इस स्पष्टीकरण से सहमत हैं। न्यूट्रिशनिस्ट्स के मुताबिक घर में बने आलू को फ्राई करके खाया जा सकता है। हालांकि, बेहतर है कि ज्यादा न खाएं। हालॉकि, समस्या इस तथ्य में निहित है कि छोटे और बड़े आलू के चिप्स को कारखानों में पैक किया जाता है और लंबी अवधि के भंडारण के लिए संसाधित किया जाता है।

वॉर के बाद कई फिल्मों से बॉक्स आफिस पर धमाल मचाएंगे ऋतिक रोशन

ऋ तिक रोशन की पिछली रिलीज फिल्म वॉर और सुपर 30 थी। जिसने बॉक्स आफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। फिल्म में ऋ तिक रोशन के किरदार को भी पसंद किया गया था। हालांकि इसके बाद से ऋ तिक रोशन की कोई फिल्म नहीं रिलीज की गई है। ऐसे में आज हम आपको ऋ तिक रोशन की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताने जा रहे है। जिससे जरिए वो बॉक्स आफिस पर धमाल मचाने वाले है। ऋ तिक रोशन की अगली फिल्म कृष 4 है। जिस पर ऋ तिक रोशन के पिता राकेश रोशन पिछले काफी समय से काम कर रहे है। फिल्म के लिए मेकर्स इन दिनों अपनी तैयारी कर रहे है। उम्मीद हैं कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। ऋ तिक रोशन जल्द ही फिल्म फाइटर में नजर आने वाले है। फिल्म में दीपिका पादुकोण पहली बार ऋ तिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली है। फाइटर का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करने वाले है। खबरों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ऋ तिक रोशन मधु मंटेना की फिल्म रामायण में नजर आ सकते है। ऋ तिक रोशन इस फिल्म में रावल के रोल में होंगे वहीं करीना कपूर खान सीता के रोल में और महेश बाबू राम के रोल में नजर आने वाले है। ऋतिक रोशन फिल्म वॉर 2 में भी नजर आने वाले है। ऐसा खबरों मे कहा जा रहा है। हालांकि अब तक मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर ऐलान हनीं किया गया है।

अक्षय और रवीना के इस आईकॉनिक गाने को सूर्यवंशी में किया जाएगा रीक्रिएट

पिछले काफी समय से बॉलीवुड के कलाकार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज अटकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म सूर्यवंशी पिछले साल मार्च के महीने में रिलीज होने वाली थी। लेकिन बाद में कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की शूटिंग को मेकर्स ने रोक दिया था। पिछले साल मार्च के महीने में अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मेकर्स ने इसकी रिलीज को रोक दिया था। दूसरी बार जब मेकर्स ने रिलीज डेट तय की तो एक बार फिर से कोरोना का कहर फिल्म पर टूट गया। इस साल मार्च के महीने में कोरोना वायरस का कहर विकराल रूप ले चुका था। जिसकी वजह से मेकर्स ने फिल्म को असमय के लिए टाल दिया है। हालांकि अब फिल्म को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सूर्यवंशी की नई रिलीज डेट 15 अगस्त तय की है। फिल्म इसी साल आजादी के मौके पर सिनेमा हॉल में रिलीज की जाएगी। हालांकि अब इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्षय कुमार और रवीना टंडन के गाने मशहूर गाने टिप टिप बरसा पानी को फिल्म सूर्यवंशी के लिए रीक्रिएट किया जाएगा। बता दें कि ये गाना अक्षय कुमार की फिल्म श्मोहराश्य का है। गाने श्टिप टिप बरसा पानीश्य को अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के साथ रीक्रिएट किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके ओरिजनल गाने में अक्षय कुमार के साथ अभिनेत्री रवीना टंडन दिखाई दी थी। ये गाना अपने समय का सबसे मशहूर गाना है। ये गाना आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। गाने में अक्षय कुमार की केमेस्ट्री रवीना टंडन के साथ काफी बेहतरीन थी।

जाम से निजात दिलाने के लिए हटाया गया अतिक्रमण

जौनपुर। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के बाबत जिला प्रशासन की ओर से बृहस्पतिवार को शाम को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत चहारसू चौराहे से लेकर ओलंदगंज तक हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क की पटरियों को खाली कराने से लेकर दर्जनों मकानों की दीवारें व बारजे आदि को तोड़े गए।

शहर में मार्गों पर हुए अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम लग रहा था। इस दौरान लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान हो रहे थे। जिससे लोगों के आवश्यक काम भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बृहस्पतिवार से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया। पहले दिन शहर के चाहरसू चौराह से लेकर ओलंदगंज तक सड़क की पटरियों पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क की पटरियों व नालियों पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। जिस पर दुकानदारों की ओर से कब्जा किया गया था। अतिक्रमण हटाने वालों में नगर पालिका व यातायात पुलिस के लोग भी शामिल रहे। नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार अग्निहोत्री का कहना है कि शहर को जाम से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाकर सड़क की पटरियों व नालियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू किया गया है। अभियान कई दिनों तक चलेगा। बृहस्पतिवार को चहारसू चौराहे से लेकर ओलंदगंज तक अतिक्रमण हटाया गया।

अतिक्रमण करने वाले 70 लोगों को भेजा गया नोटिस

जौनपुर। अब शहर के ग्रीन लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण कर बने भवनों के 70 स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में अतिक्रमण के संबंध ा में जवाब मांगा गया है। जवाब उचित नहीं मिलने पर भवनों को गिराने का कार्य किया जाएगा।

जौनपुर महायोजना 2021 में पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक व आवासीय भवन बना लिए गए हैं। सबसे अधिक अवैध अतिक्रमण नए पुल से वाजिदपुर तिराहा, चांदमारी और कंहईपुर देहात, बदलापुर पड़ाव से कलीचाबाद पुलिया, शिया कालेज से हम्जा चिश्ती तक, लाइन बाजार से खरका कालोनी तक, गंगापट्टी कला, जगदीशपुर, माधुरी चौरसिया से आदमपुर मार्ग तक, नई मंडी के पीछे भवानीपुर, प्रसाद से चौकिया मार्ग तक किया गया है। इसी तरह से नईगंज तिराहा से ईदगाह मार्ग तक, लखनपुर से सरफराजपुर तक, सीहीपुर से सैदनपुर तक, पचहटिया, मंडी मार्ग से चितरसारी रोड तक, प्रेमराजपुर मार्ग पर भी ऐसे भवन बनाए गए हैं। ऐसे व्यवसायिक व आवासीय भवनों के 70 स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब नहीं मिलने पर भवनों को गिराया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री का कहना है कि शहर के ग्रीन बेल्ट में निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है। जो भूमि जौनपुर महायोजना 2021 में पार्क के लिए आरक्षित है, उस पर अतिक्रमण करने वाले 70 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित लोगों से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। ऐसा नहीं होने पर अतिक्रमण किए हिस्से को गिरा दिया जाएगा।

शाहगंज विधायक ने सात अस्पतालों को लिया गोद

जौनपुर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सात स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लिया है। उन्होंने सभी सात स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लिए जाने का पत्र डीएम व सीएमओ को भेजा है। विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने बताया कि 22 जून को उन्होंने सीएचसी शाहगंज को गोद लिया था, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित सीएचसी खुटहन व सुईथाकलां, राजकीय महिला चिकित्सालय शाहगंज सहित पीएचसी जमुनियां, बिशुनपुर, ताखा व मदरहां आदि की हालत अत्यंत दयनीय है। पिछले चार वर्षों में इन स्वास्थ्य केंद्रों पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई, जिससे मरीजों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि डीएम व सीएमओ को पत्र के माध यम से अवगत कराया है कि उन्होंने इस सभी स्वास्थ्य केंद्रों को गोद ले लिया है। उन्होंने कहा कि उनसे जो भी संभव होगा, अपने स्तर से इन अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि अपनी क्षेत्रीय विध ायक निधि के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अस्पतालों में सभी व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त कराई जाएगी।

गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को किया गया जागरूक

जौनपुर। डॉ भीमराव आंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौहर में बृहस्पतिवार को आकांक्षा समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही उनको वजन सप्ताह ,गोद भराई, अन्नप्राशन आदि के बारे में जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि डॉ. अंकिता राज ने कहा कि गर्भावस्था में स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। समय–समय पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराते रहना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। इसके पहले तीन महिलाओं की गोद भराई व तीन बच्चों के अन्नप्राशन सहित किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए गिफ्ट हैंपर दिए गए। सीएचसी परिसर में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश मिश्र व संचालन दीपक प्रताप चौबे ने किया। इस अवसर पर मनोज कुमार वर्मा, हर्ष सिंह, राज कृष्ण शर्मा, भैयालाल, सरिता गुप्ता, रीता यादव, संजू ,संतोष गिरी, मीरा पाठक, संजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।

चालू हो पाएगा बाईपास, बचा है 130 मीटर का काम

जौनपुर। जौनपुर–आजमगढ़ एनएच पर गौराबादशाहपुर कस्बे से पांच किमी बाईपास सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसे डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 25 जून तक चालू करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया था, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। कारण, बारिश के कारण बाईपास सड़क का निर्माण कार्य धीमा पड़ गया है। अभी भी 130 मीटर सड़क बनाया जाना बाकी है। जौनपुर–आजमगढ़ एनएच पर नगर पंचायत गौराबादशाहपुर क्षेत्र के विथार गांव के पास से बाईपास चोरसंड, इकरामगंज, बमैला व गौरा गांव की तरफ से होते हुए आजमगढ़ जिले के जीवली बाजार तक बनाया जा रहा है। इस बाईपास को पीडब्लूडी की ओर से बनवाया जा रहा है। जिसकी दूरी लगभग साढ़े पांच किलोमीटर है। इस बाईपास का निर्माण पिछले तीन वर्षों से चल रहा है। बाईपास का निर्माण शीघ्र हो सके, इसके लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पिछले दिनों पहुंचकर निर्माण कार्य की जांच की थी। इस दौरान पीडब्लूडी के सहायक अभियंता अभय यादव व अवर अभियंता कुतुबुद्दीन को 25 जून तक हर हाल में बाईपास का निर्माण पूरा कर आवागमन शुरू करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद बाईपास के निर्माण में विभाग तेजी से जुट गया, लेकिन अभी भी 130 मीटर सड़क और बनाया जाना बाकी है। हालांकि जिम्मेदार बाईपास को डीएम की ओर से दिय गए समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें कितना सफल हो सकते हैं। यह तो समय बताएगा। पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर आरके द्विवेदी का कहना है कि बारिश के कारण बाईपास के निर्माण का कार्य तेजी से नहीं हो पाया है।

प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से क्षुब्ध युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान

जौनपुर। झारखंड में प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से क्षुब्ध युवक ने शाहगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार की रात मालगाड़ी से कटकर जान दे दी। उसके पास से मिले सुसाइड में लिखा है कि उसकी मौत के लिए उसकी प्रेमिका के परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सरपतहा थाना क्षेत्र के अशोकपुर कला (खेमनापुर) निवासी प्रवीण कुमार (23) पुत्र रामबुझारत ने बुधवार की रात शाहगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि वह पंजाब में नौकरी करता था। वहीं पर झारखंड निवासी एक परिवार की युवती से प्रेम हो गया। दोनों वहां से भाग निकले थे। युवती के परिजनों ने उसके खिलाफ झारखंड में अपनी पुत्री को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह जब भी झारखंड जाता था तो वहां प्रेमिका के परिजन उसकी पिटाई करते थे।

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक घनश्याम मिश्र द्वारा "जनछाया" बजरंग प्रिंटिंग प्रेस, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर से प्रकाशित

कार्यकारी सम्पादक : चंचल मिश्र

फोन : 9451117446

editorjanchhaya@gmail.com